<u>**प्रसार भारती**</u>
<u>**भारतीय प्रसारण निगम**</u>
<u>**आकाशवाणी केन्द्र शिमला**</u>
<u>**08.11.2025/प्रादेशिक समाचार/1945 बजे**</u>

मुख्य समाचार

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कानूनी दस्तावेज़ों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाने पर दिया बल।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा–सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए कई कदम।
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप–झूठ के सहारे चल रही राज्य सरकार से हर वर्ग निराश।
- बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा–एच.पी.एम.सी. उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और इनकी बिक्री बढ़ाने के प्रयास जारी।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कानूनी दस्तावेजों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाने पर बल दिया है। वे आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार ने न्याय की सुगमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ भी किया। केन्द्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधारात्मक कदम उठा रही है। हमीरपुर ज़िले में नादौन विधानसभा क्षेत्र के मंझेली और कडसाई में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रयासों से हिमाचल राष्ट्रीय शिक्षा सूचकांक में 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर मैडिकल कॉलेज को प्रदेश के सबसे आधुनिक और भव्य मैडिकल कॉलेज की तर्ज़ पर विकसित किया जा रहा है। नादौन में खेल पर्यटन विकसित करने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एक सौ 20 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश के पहले इंडोर स्टेडियम का निर्माण जारी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के तहत कांगू स्कूल को सी.बी.एस.ई. से संबद्ध करने की घोषणा की। उन्होंने मंझेली–भूंपल सड़क की डी.पी.आर. जल्द बनाने के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।

संसद सत्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पहली दिसंबर से 19 दिसम्बर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा कर रही है जो लोकतंत्र को मजबूत करने सहित देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करे।

जीएसटी

अगली पीढ़ी के जी.एस.टी. सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास सामग्री और सेवाओं पर कर में कमी की पेशकश करके आवास और निर्माण क्षेत्र को राहत प्रदान की है। नए सुधार के साथ सीमेंट पर कर की दर पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से भवन निर्माण की लागत में कमी आई है और मकान खरीददारों और डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम हुआ है।

अगलीपीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास सामग्री और सेवाओं पर कर में कमीकी पेशकश करके आवास और निर्माण क्षेत्र को राहत प्रदान की है। नए सुधार के साथ सीमेंटपर कर की दर पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से भवन निर्माण की लागत में कमी आई है और मकानखरीदारों और डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। इसके अलावा संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉकोंपर अब 12 प्रतिशत की जगह केवल 5 प्रतिशतजीएसटी लगेगा, जिससे फर्श और फिनिशिंग की लागत कम हो जाएगी। इसीप्रकार, रेत–चूने की ईंटों पर भी कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है,जिससे आवास निर्माण की लागत कम हो गई है। इसके साथ ही ईंटों के जॉब वर्कपर जीएसटी को भी 12 प्रतिशत के कर स्लैब से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण आवास की लागत कम हुई है और ईंट भट्टे चलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग– एमएसएमई को समर्थन मिला है। संशोधित ढांचे के तहत यह युक्तिकरण न केवल निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई को मजबूत कर रहा है और रोजगार पैदा कर रहा है, बल्किघरों और बुनियादी ढांचे को और अधिक किफायती भी बना रहा है।

जयराम ठाकुर

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि झूठ के सहारे चल रही प्रदेश सरकार से हर वर्ग निराश है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई हिम केयर जैसी योजना को बंद कर दिया है जिसके चलते लोग इलाज के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं या फिर इलाज ही नहीं करवा पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा सरकार ने पिछले 3 वर्षों में करीब डेढ़ हज़ार से अधिक स्कूल बंद कर दिए हैं जिससे स्थानीय बच्चों को भारी असुविधा हुई है। मीडिया में आई एक खबर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल में एक सौ 16 बच्चे ठण्ड के इस मौसम में भी तिरपाल के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने का दावा कर रही है लेकिन हकीकत इससे विपरीत है।

उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिक्षकों और अभिभावकों से बच्चों को नशे की कुरीतियों के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया है। नाहन में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ–साथ खेल व अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उद्योग मंत्री ने कहा कि शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेज़ी माध्यम आरम्भ कर दिया है। इसके अलावा अगले सत्र से प्रदेश के सौ सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सी.बी.एस.ई. बोर्ड से संचालित किया जाएगा।

जगत सिंह नेगी

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार एच.पी.एम.सी. के उत्पादों को देश में अधिक लोकप्रिय बनाने और इनकी बिक्री बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रही है। सोलन ज़िले के परवाणू में आज एच.पी.एम.सी. संयंत्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और इनमें विविधता लाने के लिए कार्यरत है। बागवानी मंत्री ने बताया कि किसानों व बागवानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और बेहतर विपणन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल–कोटखाई क्षेत्र के टिक्कर में आज करीब 7 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली कडीवन, उमलाडवार, गालून सड़क का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जुब्बल–कोटखाई क्षेत्र में करीब 5 सौ करोड़ रूपए के सड़क निर्माण व मुरम्मत कार्य प्रगति पर हैं। रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में क्षेत्र के लिए एक सौ 10 करोड़ रूपए स्वीकृत हुए हैं।

धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज प्रदान करना राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 10 नवम्बर को मण्डी में एक कार्यक्रम में आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के परिवारजनों को चार–चार लाख रूपए की राहत राशि वितरित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद प्रभावितों की राहत राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है।

हमीरपुर भाजपा

हमीरपुर ज़िला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की परिचय बैठक आज हमीरपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में मोर्चा अध्यक्ष राज कुमार ने अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए भाजपा द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान हमीरपुर ज़िला भाजपा अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली सरकारों ने प्रदेश में सड़क विकास को व्यापक प्रोत्साहन दिया जिससे दूरदराज़ और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

बैडमिंटन

मंडी में 15 और 17 वर्ष से कम आयुवर्ग की राज्यस्तरीय सब–जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता आज शुरू हुई। प्रतियोगिता के शुभारम्भ पर स्थानीय विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मण्डी शहर में इंडोर खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए करीब 22 करोड़ रूपए की डी.पी.आर. बनाकर राज्य सरकार को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस खेल परिसर के लिए मण्डी के पड्डल में 9 बीघा ज़मीन खेल विभाग के नाम की जा चुकी है।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कानूनी दस्तावेज़ों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाने पर दिया बल।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा–सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए कई कदम।
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप–झूठ के सहारे चल रही राज्य सरकार से हर वर्ग निराश।
- बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा–एच.पी.एम.सी. उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और इनकी बिक्री बढ़ाने के प्रयास जारी।